प्रसार भारती

भारतीय प्रसारण निगम

आकाशवाणी केन्द्र शिमला

06.02.2026 / प्रादेशिक समाचार / 15:00 बजे

परीक्षा पे चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों के साथ अपने लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के दौरान छात्रों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने परीक्षा के दौरान तनाव और चिंता से निपटने के तरीकों पर छात्रों को संबोधित किया। नरेन्द्र मोदी ने छात्रों को अपने स्वयं के अनूठे शिक्षण तरीकों पर भरोसा रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कोई भी दो व्यक्ति एक ही तरह से नहीं सोचते या सीखते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्र की अपनी एक अलग शैली होती है, और उन्हें अपनी तैयारी के तरीके पर पूरा विश्वास रखना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जीवन केवल परीक्षा और अंकों तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षा जीवन को आकार देने का माध्यम है, जबकि परीक्षाएं केवल स्वयं का मूल्यांकन करने का एक तरीका हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतिम लक्ष्य केवल अंक नहीं, बल्कि जीवन का संपूर्ण विकास होना चाहिए।

परीक्षा पे चर्चा –2

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कौशल को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है–जीवन कौशल और व्यावसायिक कौशल, और छात्रों को दोनों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उचित अध्ययन, अवलोकन और ज्ञान के अनुप्रयोग के बिना कोई भी कौशल प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

सर्वांगीण विकास पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शरीर और मन का विकास समान रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे व्यायाम, योग, पौष्टिक आहार, पर्याप्त आराम और मानसिक शक्ति को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।

विधायक प्राथमिकता बैठक

प्रदेश में वर्ष 2026–27 के बजट के लिए दो दिवसीय विधायक प्राथमिकता बैठकें आज से शिमला स्थित राज्य सचिवालय में हो रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इन बैठकों में प्रदेश के आठ जिलों के विधायक अपने–अपने क्षेत्र की बजट प्राथमिकताएं रखेंगे।

इससे पहले आज सुबह भाजपा विधायकों ने सरकार पर विपक्षी विधायकों की पिछली प्राथमिकताओं को नजरअंदाज करने और विधायक निधि रोकने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार अक्तूबर 2025 के बाद से विधायक क्षेत्र विकास निधि जारी नहीं कर रही है, जिससे विधायकों को अपने–अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनता से किए गए विकास कार्यों के वादे पूरे करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले तीन वर्षों से विपक्षी विधायकों द्वारा दी गई विकास प्राथमिकताओं पर न तो डीपीआर बनाई जा रही है और न ही उन्हें नाबार्ड को स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था और समान विकास की भावना के विपरीत है।

विधायक प्राथमिकता बैठक–2

इस मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख्खू ने कहा कि अच्छा होता अगर भाजपा विधायक दल प्रदेश के लिए रुके राजस्व घाटा अनुदान–आरडीजी की बहाली के लिए लोकभवन शिमला में राज्यपाल के पास जाता।

———————————————————————————————————